VISION IAS

www.visionias.in

VISION IAS
R N 14 DEC 2021 NO. 03
RECEIVED

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1514)

Name of Candidate	AMAR MEENA		
Medium Eng./Hindi	HINDI [हिंदी]	Registration Number	27244
Center	ORN	Date	14/12/21

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
   इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

1. Highlighting the changes introduced by the Government of National Capital Territory of Delhi (GNCTD) Amendment Act, 2021, analyse various issues with the amended Act. **(150 words) 10**

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (GNCTD) संशोधन अधिनियम, 2021 द्वारा प्रारंभ किए गए परिवर्तनों को रेखांकित करते हुए, इस संशोधित अधिनियम से जुड़े विभिन्न मुद्दों का विश्लेषण कीजिए।

हाल ही में संसद ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (GNCTD) संशोधन अधिनियम पारित किया। जिसकी दिल्ली सरकार ने आलोचना की।

मुख्य प्रावधान →

(i) दिल्ली सरकार का अर्थ उप राज्यपाल (LG) होगा।

(ii) मुख्यमंत्री तथा मंत्रीपरिषद् को किसी भी कार्यकारी निर्णय जिसमे नियम निर्माण भी शामिल है कि पूर्व सूचना उपराज्यपाल को को देनी होगी।

* ज्ञातव्य हो संविधान में 69 वाँ संशोधन करके दिल्ली में विधान-सभा की स्थापना कि गयी थी। और अनुच्छेद 239 AA को स्थापित किया गया था।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

वर्तमान संशोधन से जुड़े मुद्दे :→

(1) सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रतिकूल जिसमें पुलिस, कानून-व्यवस्था और भूमि के अतिरिक्त सभी राज्य व समवर्ती सूची के विषयों पर दिल्ली विधानसभा का अधिकार माना गया।

(2) दिल्ली सरकार की लोकतांत्रिक स्थिती को कमजोर करता है।

(3) सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ

(4) LG - वास्तविक जन प्रतिनिधि नहीं है।

आगे की राह :→

(1) (NCTD) दिल्ली में सहयोगी संघवाद तथा परस्पर विश्वास पर राज्य व केंद्र सरकार को कार्य करना चाहिये।

(2) किसी भी विवाद से विश्वास (जनता) को ठेस पहुँचती है।

दिल्ली की विशिष्ट स्थिती के कारण दिल्ली सरकार तथा केंद्र को मिलकर व्यापक सहयोग की आवश्यकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. Are there valid arguments for continuing with sedition law in 21st century democratic India? Discuss in light of the debate surrounding it.

(150 words) 10

क्या 21वीं सदी के लोकतांत्रिक भारत में राजद्रोह कानून को जारी रखने के लिए वैध तर्क विद्यमान हैं? इससे संबंधित वाद-विवाद के आलोक में चर्चा कीजिए।

भारत में राजद्रोह कानून IPC-124 (A) को ब्रिटीश राज में बनाया गया था, ताकि स्वतंत्रता संग्राम से निपटा जा सके।

राजद्रोह कानूनों को हटाने के पक्ष में तर्क :→

(1) निम्न दोष सिद्धि दर → पिछले 5 वर्षों में सिर्फ 2 मामलों में दोष सिद्धी।

(2) राजनैतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल की प्रवृत्ति

(3) विरोध की आवाज को दबाने में प्रयोग - उदाहरण के लिये CAA-कानून विरोध प्रदर्शनों, किसान आंदोलन

(4) संविधान के अनुच्छेद-19 में उल्लेखित वाक् अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ।

(5) अस्पष्ट शब्दावली के कारण दुरुपयोग का

साधन बन जाता है।

बनाये रखने के पक्ष में :→

(1) राज्य को स्वयं की सुरक्षा का अधिकार
(2) कानून - व्यवस्था तथा सरकारों की स्थिरता में सहायक
(3) शत्रु राज्यों के विरुद्ध स्वयं की रक्षा
(4) नागरिक अधिकारों की एक सीमा है।

आगे की राह

(1) विधि आयोग ने IPC - 124(A) को जारी रखने की सिफारिश की है। - बशर्ते इसका उपयोग मनमाना न हो।
(2) "विरोध को विद्रोह से अलग देखा जाना चाहिये। पहला शब्द रचनात्मक है वहीं दूसरा विध्वंसात्मक।" - जस्टिस दलबीर भंडारी

3. Identify the issues that have contributed to a decline in the performance of Parliamentary Standing Committees. How can these issues be addressed? **(150 words) 10**

उन मुद्दों की पहचान कीजिए जिन्होंने संसदीय स्थायी समितियों के प्रदर्शन में गिरावट में योगदान दिया है। इन मुद्दों का समाधान कैसे किया जा सकता है?

संसदीय स्थायी समितियाँ भारतीय लोकतंत्र में रचनात्मक बहस तथा विचार-विमर्श हेतु बनायी गयी हैं।

स्थायी समितियों के प्रदर्शन में गिरावट :

कारण

① COVID-19 संकट के कारण बैठकों का न हो पाना

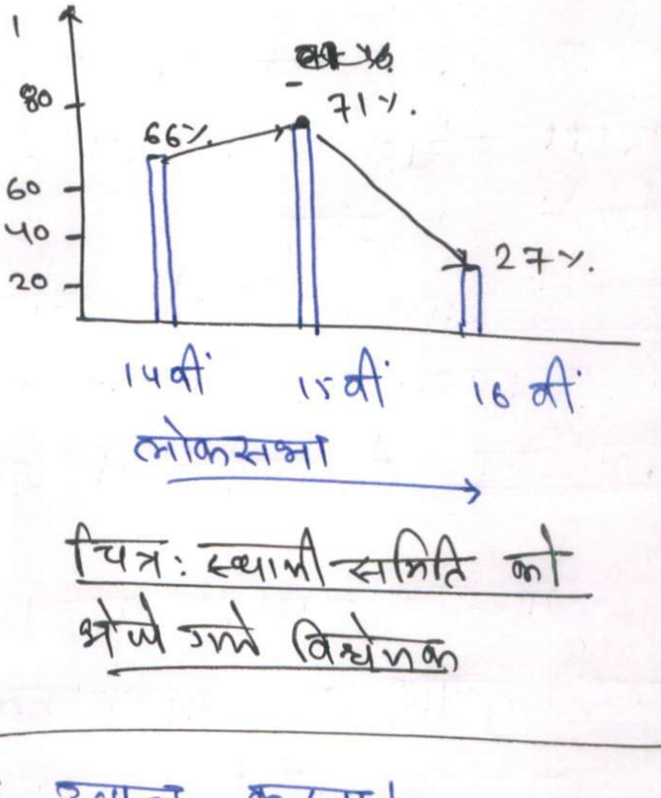

चित्र: स्थायी समिति को भेजे गये विधेयक

② विपक्ष द्वारा संसदीय कार्यवाही में अवरोध उत्पन्न करना।

③ सरकार का असंवेदनशील रवैया (विपक्ष के खिलाफ)

(4) विपक्ष को बोलने के लिये समय कम दिया जाना जिससे व्यवधान उत्पन्न होना।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(5) कमजोर विपक्ष तथा बहुमत वाला केंद्र

समाधान के उपाय :→

(i) संसदीय कार्यवाही हेतु कैलेण्डर निर्माण
(2) संविधान समीक्षा आयोग (2002) की सिफारिशें मानना → न्यूनतम बैठकों की संख्या का निर्धारण 100 राज्य सभा तथा 120 - लोकसभा
(3) प्रत्येक सदस्य को अधिक समय आवंटन
(4) हाइब्रिड संसद → वर्चुअल तथा भौतिक बैठकों के द्वारा
(5) स्थायी समितियों को विधेयक भेजने की परम्परा का निर्माण करना।
(6) गिलोटिन के प्रयोग से बचना।

भारतीय संसदीय परम्पराओं में निरंतर सुधार की आवश्यकता है जिसमें हमें अमेरिका तथा ब्रिटेन संसदीय सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं से सीख सकते हैं।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. Despite being a non-constitutional body, the Prime Minister's Office (PMO) has wielded immense decision-making power in India. Discuss the advantages and issues associated with it. (150 words) 10

एक गैर-संवैधानिक निकाय होने के बावजूद, प्रधान मंत्री कार्यालय (PMO) के पास भारत में निर्णय-निर्माण की व्यापक शक्ति है। इससे संबद्ध लाभों और मुद्दों पर चर्चा कीजिए।

(PMO) प्रधानमंत्री कार्यालय वस्तुत: भारत की "किचन कैबिनेट" के समान ही है।

PMO के ~~शक्ति~~ निर्णय निर्माण की शक्ति के लाभ

① त्वरित निर्णय लेने में

② PMO में तकनीकि तथा विशेषज्ञों का समूह होता है जो कि प्रत्यक्ष-त: राजनीति में आये बगैर अपना योगदान देते हैं

③ प्रधानमंत्री चूंकि सरकार के वास्तविक (de facto) मुखिया हैं ऐसे में उन्हें विशेषज्ञों की सलाह जरूरी ताकि निर्णय निर्माण सुगम व सही हो

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

मुद्दे

① PMO न तो संवैधानिक संस्था है न ही सांविधिक।

② संविधान में मंत्रिपरिषद् का उल्लेख है अतः अनौपचारिक PMO का मंत्रिपरिषद पर प्रभुत्व ठीक नहीं।

③ PMO के अधिकारी जनता अथवा विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं।

④ PMO का बहुमत प्राप्त दल में एक गैर-लोकतांत्रिक स्वरूप है।

वस्तुतः तमाम आलोचनाओं के बावजूद PMO द्वारा प्रधानमंत्री को आवश्यक तथा तकनीकी मामलों पर त्वरित सलाह मिलती है जो कि विकास हेतु जरूरी है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. Discuss the role of data in governance in India. Also, state the various challenges in this regard and suggest remedial measures.

(150 words) 10

भारत में शासन में डेटा की भूमिका पर चर्चा कीजिए। साथ ही, इस संबंध में विद्यमान विभिन्न चुनौतियों का उल्लेख कीजिए एवं उपचारात्मक उपायों का सुझाव दीजिए।

वर्तमान में डेटा किसी भी सदी की सरकारों तथा नागरिकों के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बन गया है।

शासन में डेटा की भूमिका:-

(1) नीति निर्माण में → डेटा द्वारा साक्ष्य आधारित नीति निर्माण किया जा रहा है जो बेहतर नीति निर्माण हेतु अपेक्षित है।

(2) नीतियों तथा कार्यक्रमों की मॉनीटरिंग में → रियल टाइम-मानीटरिंग द्वारा नीतियों की समीक्षा तथा सुधार

(3) सेवाओं की प्रभावी सुपुर्दगी में - लाभ भोगियों की पहचान तथा

एकल बिंदु योजना का चयन।
eg. PM-उज्ज्वला योजना में 6 करोड़ से अधिक लाभभोगियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण।

④ भ्रष्टाचार निवारण → लीकेज प्रतिबंध

⑤ सरकारी पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता बनाने में।

चुनौतियाँ →
① प्रशिक्षण का अभाव
② अवसंरचना का अभाव
③ कार्मिकों की डेटा को अपनाने के प्रति अनिच्छा
④ पुराने रिकार्डों के डिजिटलीकरण न होना।
⑤ डेटा प्राइवेसी बिल का पारित न होना।

उपचारात्मक उपाय →
① डेटा कानून बनाना
② डिजिटल अवसंरचना विकास
③ कार्मिक प्रशिक्षण
④ जनता में डिजिटल शिक्षा प्रसार
⑤ निजता का सम्मान व संरक्षण

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. With specific examples, elaborate upon the conditions that led to the emergence of a new civil society in urban India in the last few decades. Also, highlight its contribution towards effecting governance and policy changes. **(150 words) 10**

विशिष्ट उदाहरणों के साथ, उन परिस्थितियों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए जिनके कारण पिछले कुछ दशकों में शहरी भारत में एक नए नागरिक समाज का उदय हुआ है। साथ ही, शासन और नीतिगत परिवर्तनों को प्रभावित करने में इसके योगदान पर प्रकाश डालिए।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. The Gati Shakti mission has the potential to not only address the issue of infrastructure bottlenecks but also streamline the governance processes in the country. Elucidate. **(150 words) 10**

गति शक्ति मिशन में न केवल अवसंरचना संबंधी बाधाओं का समाधान करने की क्षमता है अपितु देश में शासन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने की भी क्षमता विद्यमान है। स्पष्ट कीजिए।

भारत सरकार ने ~~वर्ष 2020-21~~ अगस्त 2021 में गति शक्ति मिशन की घोषणा की।

गति शक्ति मिशन

→ भारत में अवसंरचना विकास

→ गैस पाईपलाइन, कार्गो हैंडलिंग डिपोस तथा औद्योगिक गलियारों के निर्माण की आधारशिला रखती है।

→ गाँवों में 5G कनेक्टिविटी हेतु भी प्रावधान है।

शासन प्रक्रियाओं में गति शक्ति मिशन :

① निर्यात प्रोत्साहन के कारण विभिन्न शुल्कों तथा सीमा अवरोधों व अनुमतियों से राहत।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

② बंदरगाह अवसंरचना विकास तथा कार्गो हैंडलिंग तक सभी अनुमतियाँ एक स्थान पर उपलब्ध

③ ग्रामीण भारत में 4G कनेक्टिविटी e-प्रशासन (e-governance) को मजबूत करेगी।

इस प्रकार गतिशक्ति परियोजना न सिर्फ अवसंरचना को मजबूत करेगी बल्कि प्रशासन में सुधार भी करती है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. Giving an account of the issues faced by workers in the informal sector, discuss whether the recently launched e-Shram portal can help in addressing them. **(150 words) 10**

अनौपचारिक क्षेत्रक में श्रमिकों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं का विवरण देते हुए चर्चा कीजिए कि क्या हाल ही में प्रारंभ ई-श्रम पोर्टल उनका समाधान करने में सहायता कर सकता है।

भारत में लगभग 88% श्रम बल अनौपचारिक क्षेत्रक में संलग्न है। (ILO- 2019)

अनौपचारिक क्षेत्रक में श्रमिकों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ:-

① सामाजिक सुरक्षा का अभाव - कोई बीमा इत्यादि नहीं।

② कम मजदूरी पर कार्य करना

③ कार्यस्थल पर दुर्घटना का मुआवजा नहीं।

④ आय तथा नौकरी की सुरक्षा नहीं।

⑤ कार्य की कठोर दशायें - सामान्यतः औपचारिक श्रमिकों से मुश्किल काम के घंटे।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(6) पेंशन तथा वृद्धावस्था में आय की असुरक्षा → किसी पेंशन योजना का भाग नहीं होते।

(7) संगठित नहीं हो पाते व कम मोल-भाव की क्षमता।

ई-श्रम पोर्टल के लाभ

(1) विभिन्न पेंशन योजनाओं के विकल्प

(2) सामाजिक सुरक्षा व बीमा योजना-ओं के लाभ।

इसी कड़ी में भारत सरकार द्वारा 4-श्रम ~~का~~ कानूनों को संहिताबद्ध किया है ताकि श्रमिक कल्याण हो सके। संविधान का अनुच्छेद 43(B) भी यही कहता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. Clarifying the significance of the recent developments on the issue of global minimum tax, discuss its prospects and challenges for India.

(150 words) 10

वैश्विक न्यूनतम कर के मुद्दे के संदर्भ में हालिया घटनाक्रमों के महत्व को स्पष्ट करते हुए, भारत के लिए इसकी संभावनाओं और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।

हाल ही में G-20 राष्ट्रों द्वारा एक वैश्विक न्यूनतम कर 15% की चर्चा की गयी।

(i) यह बहुराष्ट्रीय कम्पनीयों पर न्यूनतम 15% कॉर्पोरेट कर की अवस्थापना रखता है।

(ii) साथ ही बहुराष्ट्रीय कम्पनीयाँ (MNC) अब जिन राष्ट्रों में कार्य (operate) करती है वहाँ भी कर अदा करेंगी न कि जहाँ इनका मुख्यालय है।

महत्व — (i) टैक्स हेवन राष्ट्रों को हतोत्साहित कर एक कर-युद्ध को समाप्त करना।

(ii) MNC's के बढ़ते प्रभुत्व तथा कर-चोरी पर अंकुश लगाना।

(iii) covid-19 के बाद हुयी राजस्व हानियों को वसूलना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

भारत में संभावित लाभ :→

(i) भारत में मौजूदा प्रभावी कार्पोरेट दर 22.5% के लगभग है अत: लाभ होगा।

(ii) WEF के अनुमान से भारत को लगभग 8-13,000 करोड़ का संभावित लाभ होगा।

(iii) कर-चोरी के मामलों में कमी होगी।

चुनौतियाँ

(i) MNC's तथा टेक कम्पनियों के राजस्वों की गणना करना कठिन कार्य

(ii) भारत को मानव संसाधनों की कुशलता तथा क्षमता निर्माण की आवश्यकता है।

भारत को न्यूनतम वैकल्पिक कर का हालांकि बहुत अधिक लाभ नहीं होगा। फिर भी यह एक स्वागत योग्य कदम है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. Announcement of the AUKUS security pact heralds a new era of global geo-politics. Comment. Also, discuss how it may affect India's interests.

(150 words) 10

AUKUS सुरक्षा समझौते की घोषणा ने वैश्विक भू-राजनीति के एक नए युग की शुरुआत की है। टिप्पणी कीजिए। साथ ही, चर्चा कीजिए कि यह भारत के हितों को कैसे प्रभावित कर सकता है।

हाल ही में इंडो - प्रशांत भू-राजनीति में एक नये बहुपक्षीय संगठन का निर्माण ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन तथा अमेरिका द्वारा किया गया है।

वैश्विक भू-राजनीति पर प्रभाव :→

① चीन के बढ़ते प्रभाव को हिंद-प्रशांत में कम करना।

② अमेरिका के प्रति पूर्व NATO सदस्यों का विश्वास घटना क्योंकि AUKUS ने फ्रांस के सामरिक व रक्षा निर्यात पर प्रतिकूल असर डाला है।

③ क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया का परमाणु पनडुब्बी प्राप्त करना क्षेत्र की

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

भू राजनीति प्रभावित करेगा।

भारत पर प्रभाव :→

सकारात्मक :	नकारात्मक
① चीनी प्रभाव को कम करेगा ② क्वाड के पूरक के तौर पर AUKUS की भूमिका व्यापक है ③ भारत-फ्रांस के साथ महत्वपूर्ण सामरिक तथा रक्षा सहयोग बढ़ा सकता है	① भारत क्षेत्र में मिला सुरक्षा प्रदाता है। ऐसे में यह उसकी क्षेत्रीय आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं। ② भारत को इसमें न शामिल किया जाना - इसके सामरिक उद्देश्यों पर अंगुली उठाता है

अमेरिका को हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत जैसे लोकतंत्र को अनदेखा नहीं करना चाहिये। साथ ही मित्र राष्ट्रों के प्रति विश्वास बहाली के उपाय किये जाने चाहिये।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. Effective devolution of finances is an important requirement for Panchayati Raj Institutions (PRIs) to fulfill their objectives. Discuss while also elaborating on the reasons behind lack of financial resources for PRIs in India. **(250 words) 15**

पंचायती राज संस्थाओं (PRI) को अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वित्त का प्रभावी हस्तांतरण एक महत्वपूर्ण अनिवार्यता है। भारत में PRIs के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी हेतु उत्तरदायी कारणों का वर्णन करते हुए चर्चा कीजिए।

भारत में पंचायती राज संस्थाओं को भाग - IX तथा IX (B) में 73वें तथा 74वें संविधान संशोधनों के माध्यम से शामिल किया गया।

पंचायती राज संस्थाओं के वित्तयन के स्त्रोत :→

(1) केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा
(2) राज्य वित्त आयोग द्वारा
(3) केंद्रीय प्रायोजक योजनाओं द्वारा
(4) कराधान द्वारा

चित्र: पंचायती राज संस्थाओं की प्रमुख चुनौतियाँ

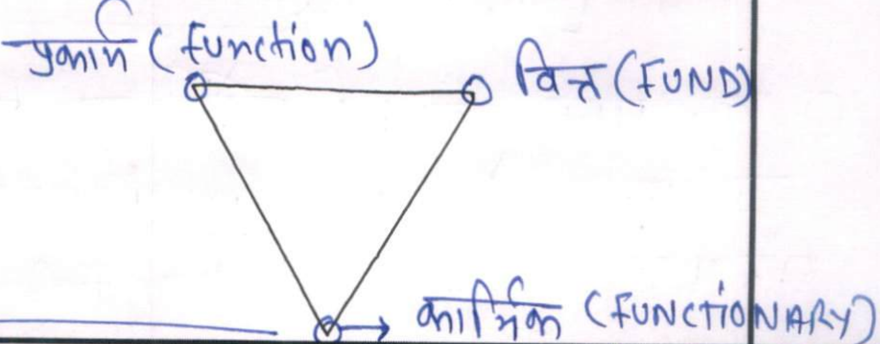

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

प्रभावी हस्तांतरण की आवश्यकता :→

(1) विकासात्मक कार्यों के क्रियान्वयन में।

(2) प्रभावी लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण में

(3) समुदायों के सशक्तिकरण हेतु

(4) ग्राम विकास हेतु → अवसंरचना निर्माण
→ गरीबी उन्मूलन
→ कृषि विकास

(5) क्षेत्रीय अवसंरचना अन्तराल को पूरा करने में → ग्रामीण व शहरी

(6) पलायन को रोकने में → रोजगार
→ शिक्षा
स्वास्थ्य सुविधाओं द्वारा

~~प्रभावी~~ **वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण :→**

① कराधान की शक्तियों का निम्न प्रयोग → केवल 6% पंचायती राज संस्थायें प्रयोग करती हैं। (नीति आयोग,

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

② करारोपण की वसूली हेतु - कुशल कार्मिकों का अभाव।

③ प्रभावी वित्तीय शक्तियों का राज्य सरकारों का स्वयं के पास रखना।

④ अपर्याप्त वित्तीय आवंटन

⑤ केंद्रीय योजनाओं के आवंटन में - "वन साइज फिट फोर ऑल" दृष्टिकोण।

आगे की राह

- वित्तपन संबंधी शक्तियों का प्रभावी विकेंद्रीकरण किया जाये।
- प्रभावी प्रशिक्षण दी जानी चाहिये। → योजना निर्माण → बजट निर्माण → वित्तीय शिक्षा

हालांकि भारत सरकार ने 15वें वित्त आयोग की सलाह पर पंचायती राज संस्थाओं के आवंटन में वृद्धि की है लेकिन आवश्यकता आत्मनिर्भरता की है

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. Judicial activism is a necessary tool to guard against "legislative adventurism and executive excesses". Critically discuss in the context of the doctrine of separation of powers as provided in the Constitution of India.

(250 words) 15

"विधायी जोखिम और कार्यकारी अतिक्रमण" से रक्षा के लिए न्यायिक सक्रियता एक आवश्यक उपकरण है। भारत के संविधान में यथा प्रदत्त शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के संदर्भ में समालोचनात्मक चर्चा कीजिए।

न्यायिक सक्रियता से ~~आशय~~ न्याय पालिका का विधायी निर्वात तथा कार्यकारी अकर्मण्यता के कारण मजबूरन ~~उनके~~ उनका स्थान लेने से है।

उदाहरण: दिल्ली में 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाना।

न्यायिक सक्रियता के उत्प्रेरक:-
(i) जनहित याचिकायें
(ii) न्यायिक समीक्षा

विधायी जोखिम में प्रति न्यायिक सक्रियता ~~के~~ :→

(i) जब विधायिका ~~निर्णय~~ निर्माण में विफल हो जाती है तब जनता का लोकतंत्र में भरोसा कम हो जाता है ऐसे में न्याय पालिका न्यायिक सक्रियता दिखाकर विधायन

का कार्य करने लगती है।

उदाहरण :→ विशाखा गाईड लाइन

कार्यकारी अतिक्रमण से रक्षा में न्यायिक सक्रियता :-

(1) सरकार द्वारा जब कानून का दुरुपयोग अथवा मनमाना उपयोग किया जाता है तब न्यायपालिका कार्यपालिका पर अंकुश लगाने के लिये अपनी सक्रियता दिखाती है।

उदाहरण: COVID-19 के दौरान आकस्मिक संकट में न्यायपालिका द्वारा निभाई गयी भूमिका।

नियंत्रण व संतुलन →

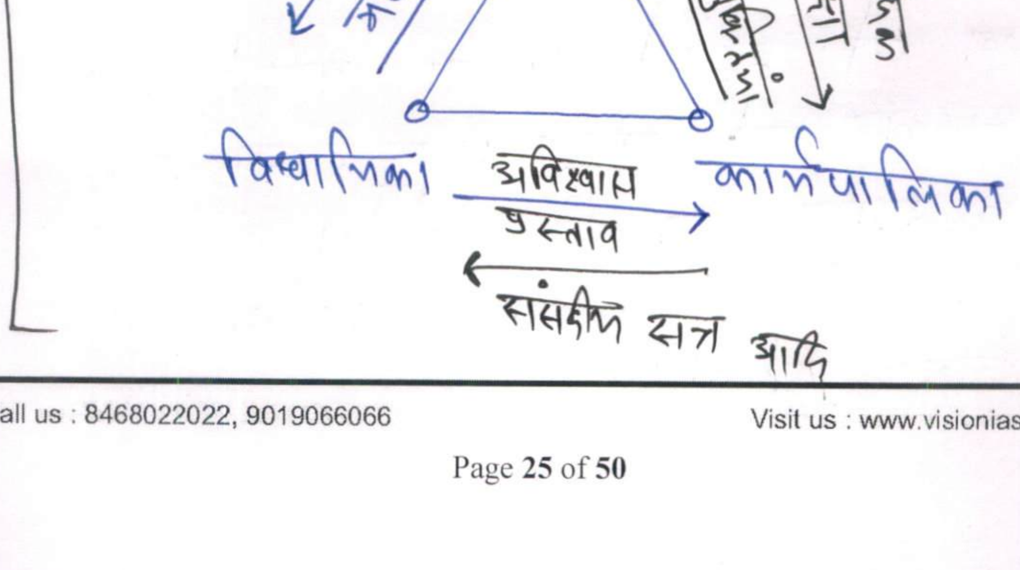

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

आलोचना :→

(i) शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत के अनुकूल नहीं।

(ii) न्यायिक सक्रियता विधायिका व कार्यपालिका को भी मौका देती है कि वे न्यायिक कार्यों में हस्तक्षेप करें। चूंकि 3 करोड़ मामले लम्बित हैं।

(iii) न्यायाधीश - प्रशासनिक तथा राजनैतिक विशेषज्ञ नहीं हैं।

(iv) न्यायपालिका लोकतांत्रिक संस्था नहीं। जबकि कार्यपालिका व विधायिका जनता के प्रति जवाबदेह हैं।

आगे की राह

(i) अंतिम उपाय के तौर पर ही न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना चाहिये।

(ii) सरकार को अग्रसक्रिय रहना चाहिये ताकि इसकी नौबत ही न आये।

(iii) न्यायपालिका को प्रथमतः सलाहकारी ही निर्णय लेने चाहिये।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. The electoral bond scheme is part of what appears to be a growing trend away from transparency and accountability in electoral funding. Critically analyse. **(250 words) 15**

चुनावी बॉण्ड योजना उस बढ़ती हुई प्रवृत्ति का भाग है जो चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता और जवाबदेही से दूर जाने की प्रतीत होती है। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

चुनावी बांड योजना के तहत राजनैतिक दलों के वित्तपन को औपचारिक माध्यमों द्वारा कर चुनावी वित्तपन में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया जाता था।

चुनावी बांड योजना के लाभ :→

(1) दलों द्वारा नकद-लेन देन में कमी।

(2) औपचारिक स्त्रोतों से वित्तपन के कारण काले धन में कमी।

(3) 86% कुल चुनावी वित्त का बांड के माध्यम से आना योजना की सफलता का सबूत।

(4) ~~इस~~ इससे चुनावी दलों के वित्तपन पर आसानी से नजर रखना संभव।

(5) दानकर्ताओं की राजनैतिक उत्पीड़न से रक्षा।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

चुनावी बांड योजना द्वारा उत्पन्न चुनौतियाँ :→

(1) पारदर्शिता संबंधी →

↳ दान दाता के विषय में जानकारी गोपनीय रखी गयी है इससे धन के स्रोत की जानकारी नहीं मिलती।

↳ काले धन की समस्या का समाधान नहीं करता।

(2) जवाबदेहिता संबंधी →

↳ 4/5 करीब चुनावी बांड सत्ताधारी दल को मिले इससे राजनैतिक लाभ के वश दान-देनी की प्रवृत्ति दिखती है।

↳ यह योजना लाभ अथवा हानि में चल रही सभी कम्पनीयों को चुनावी दान देने की अनुमति प्रदान करती है।
↳ इससे "भ्रष्टाचार" का विकास

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

होता है।

इस प्रकार चुनावी बांड योजना में व्याप्त कमियाँ भारतीय लोकतंत्र के लिये एक खतरा उत्पन्न करती है।

आगे की राह

(i) द्वितीय प्रशासनिक आयोग की सलाह के अनुरूप राजनैतिक दलों की राज्य प्रायोजित फंडीग की जानी चाहिये।

(ii) एक समय में चुनाव द्वारा धन तथा समय की बचत की जा सकती है।

(iii) जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में संशोधन कर धन-बल के प्रयोग को चुनावी अपराध घोषित किया जाये।

(iv) सूचना का अधिकार (RTI) अधि. 2005 में राजनैतिक दलों को भी शामिल किया जाये।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. The significance of the principle of subsidiarity was well reflected in the management of the COVID-19 pandemic. Analyse. **(250 words) 15**

समनुषंगिता (सब्सिडियरिटी) के सिद्धांत का महत्व कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में बेहतर रूप से परिलक्षित हुआ है। विश्लेषण कीजिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. Social media has ushered in greater transparency and accountability in governance. But accountability through social media is no alternative to institutional accountability. Analyse. **(250 words) 15**
सोशल मीडिया ने शासन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की शुरुआत की है। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जवाबदेही संस्थागत जवाबदेही का विकल्प नहीं है। विश्लेषण कीजिए।

सोशल मीडिया से तात्पर्य मीडिया के उस स्वरूप से है "जो इंटरनेट द्वारा जनता के द्वारा प्रदत्त, प्रेक्षित, ग्रहण तथा विश्लेषण किये जाने वाला ज्ञान तथा सूचना का प्रतिनिधित्व करता हो।"

सोशल मीडिया का शासन में योगदान

(1) पारदर्शिता लाने में :- सरकारी कार्यों की जनता द्वारा समीक्षा करना तथा इसे सोशल मीडिया पर डालना।
- सरकारी नीतियों तथा कार्यों के प्रति जागरूकता प्रसार।

(2) जवाबदेहिता :-
→ सरकार से प्रश्न पूछने
- महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रभावी

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

विपक्ष की भूमिका निभाने ।
के कारण सरकार की जवाबदेहिता तय की जाती है

③ प्रशासन तथा सरकार की नीतियों संबंधी जागरूकता प्रसार के कारण ~~सुशा~~ सुशासन में भी योगदान मिलता है

संस्थागत जवाबदेहि

- संस्थागत जवाबदेहि से तात्पर्य संस्थाओं के आंतरिक जवाबदेहि ढांचे ~~की ओर~~ से है दुसरे शब्दों में जब जवाबदेहि को संस्थायें एक ठोस मूल्य के तौर पर अपना लें अथवा सूची बद्ध करलें तो यह संस्थागत जवाबदेहि कहलाती है

उदाहरण - कार्यपालिका की विधायिका के प्रति जवाबदेहि।

आवश्यकता -

① जवाबदेहिता को एक प्रशासनिक मूल्य के तौर पर स्वीकृती।

② सोशल मीडिया की बजाय अधिक व्यापक। चूंकि केवल 24% इंटरनेट उपयोग-कर्ता।

③ सुशासन के एक मूल्य के तौर पर।

④ संस्थागत जवाबदेहिता सेवाओं की प्राप्ती तथा गुणवत्ता की गारंटी प्रदान करती है।

पारदर्शिता ⇄ जवाबदेहिता

इसमें आवश्यकता सोशल मीडिया तथा संस्थागत जवाबदेहिता के अपूर्व मिश्रण की है इसी से। सुशासन मजबूत होता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. Although the State has the right incentives and intentions to deliver public services efficiently, its capacity to do so is questionable. Critically discuss in the context of India. **(250 words) 15**

यद्यपि राज्य के पास सार्वजनिक सेवाओं के कुशलतापूर्वक वितरण हेतु उचित प्रोत्साहन और उद्देश्य विद्यमान हैं, तथापि ऐसा करने की उसकी क्षमता संदिग्ध है। भारत के संदर्भ में समालोचनात्मक चर्चा कीजिए।

भारत एक लोककल्याणकारी राज्य है, तथा इसी के कारण सरकार की जिम्मेदारियाँ नागरिकों के प्रति बढ़ जाती हैं।

चित्र: सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में चुनौतियाँ

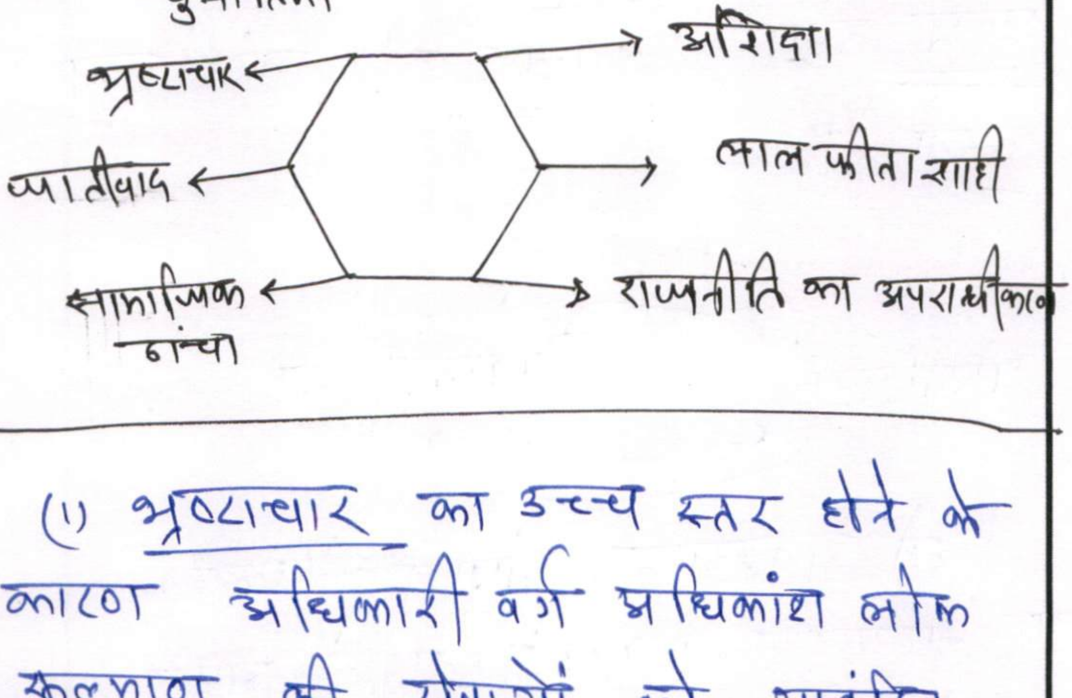

(1) भ्रष्टाचार का उच्च स्तर होने के कारण अधिकारी वर्ग अधिकांश लोक कल्याण की सेवाओं को आवंटित स्थान का गबन कर जाता है

66 वाँ स्थान करप्शन परसेप्शन इंडेक्स (2020)।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(2) व्यापक अशिक्षा : लगभग 25% आबादी में अशिक्षा होना। इसके कारण अधिकांश लाभ योगियों में कल्याणकारी योजनाओं के विषय में जागरूकता की कमी है।

(3) जातीवाद तथा प्रभु जातियों का अस्तित्व:- दलितों के प्रति भेदभाव के कारण कई दफा उन्हें सरकारी योजनाओं में पीछे छूट जाने का खतरा रहता है।

(4) लालफीता शाही : औपनिवेशिक मानसिकता के कारण भारतीय नौकरशाही में करुणा तथा संवेदना की कमी है तथा नियमों के साथ कठोरता से बंधे रहने की प्रवृत्ति है।

> उदाहरण : संतोषी नामक बालिका के आधार कार्ड न होने के कारण छत्तीसगढ़ में भुखमरी से मौत।

(5) राजनीति का अपराधीकरण → इससे भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

⑧ भारत का विकृत सामाजिक ढांचा :-
इसके कारण महिलाओं का सबसे सुभेद्य समूह बनता है और बावजूद इसके इन्हें लाभ वंचित रहना पड़ता है।

सरकारी पहलें

① प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण
② जन - धन - आधार त्रिमूर्ति योजना
③ PM - आशा योजना, PM - किसान योजना
④ एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना
⑤ सिविल सेवाओं में सुधार हेतु - मिशन कर्मयोगी।
⑥ मनरेगा में ग्राम पंचायतों को लाभ भोगियों की पहचान का दायित्व।

हालांकि अभी भी 22% के करीब ~~बेड़~~ गरीबी की दर तथा विश्व भूखमरी सूचकांक में 101/116 स्थान आगे लंबी राह तय करने की सूचना देता है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. The problem of hunger in India does not lie in food production but various other underlying issues. Discuss in the wake of decline in India's ranking in the Global Hunger Index, 2021. **(250 words) 15**

भारत में हंगर (भूखमरी) की समस्या खाद्य उत्पादन में नहीं बल्कि अन्य कई अंतर्निहित मुद्दों के कारण है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, 2021 में भारत की रैंकिंग में गिरावट के आलोक में चर्चा कीजिए।

हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स, 2021 में भारत को 101/116 वाँ स्थान मिला।

हालांकि भारत विश्व का लगभग सभी खाद्यान्नों में पहला अथवा दूसरा खाद्य उत्पादक स्थान है।

भारत में भूखमरी के कारण :→

① व्यापक गरीबी का होना → भारत में आज भी 22% (लगभग) जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है।

② करोना संकट के कारण गरीबी में वृद्धि तथा आय में कमी।

③ क्षेत्रीय असमानताओं का व्याप्त होना - बिहार में 51% बहुआयामी

निर्धनता होना वहीं केरल में [0.71%] बहुआयामी निर्धनता होना [नीति आयोग]।

(4) भारतीय खाद्य व्यवहार में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होना :-

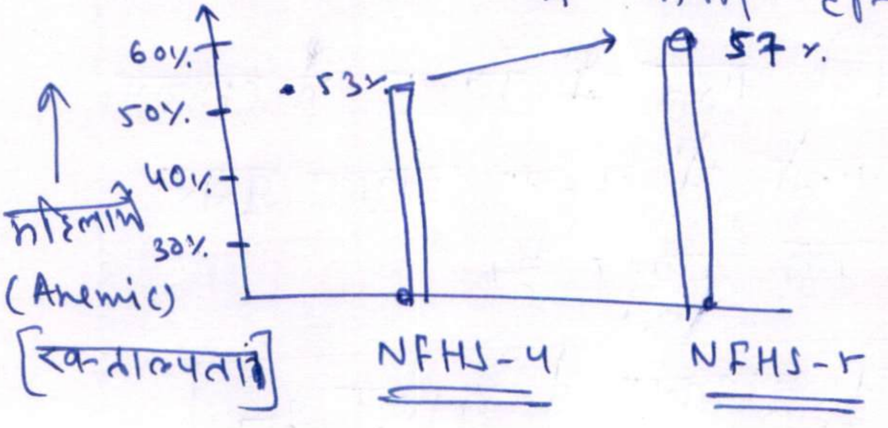

(5) भारत के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम में सूक्ष्म पोषक तत्वों पर पर्याप्त ध्यान न दीया जाना।

(6) COVID-19 के कारण मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में बाधा आना।

(7) (WASH) जल तथा स्वच्छता का निम्न स्तर → भारत में केवल 37% आबादी को स्वच्छ जल

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

तक पहुँच प्राप्त है। (WEF - 2019)

- इसके कारण भारत में प्रतिवर्ष 20 लाख बच्चे प्रभावित होते हैं।

उपाय

① सरकार द्वारा "वन नेशन वन राशन कार्ड" की घोषणा।

② भारत सरकार द्वारा "हर घर नल से जल योजना तथा Pm- जल जीवन मिशन की स्थापना।

③ पोषण स्तर सुधारने के लिये :- राष्ट्रीय पोषण सुरक्षा योजना शुरु करना।

हालांकी भूख (SDG-1) के तहत संधारणीय विकास लक्ष्य है ऐसे में भारत को ~~अधिक~~ अब और तेजी से कार्य करने की जरूरत है।

18. Democratization of primary healthcare is indispensable for fulfilling the objectives of equitable and comprehensive care in India. Discuss.

(250 words) 15

भारत में समान और व्यापक देखभाल के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का लोकतंत्रीकरण अपरिहार्य है। चर्चा कीजिए।

भारत ने समान व व्यापक देखभाल हेतु WHO की "अल्माआटा घोषणा" पर हस्ताक्षर किये हैं

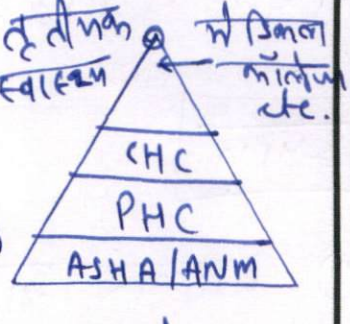

चित्र: भारत में स्वास्थ्य ढांचा

मौजूदा देखभाल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य ढाँचा :→

(i) आशा व ANM
(ii) स्वास्थ्य तथा वेलनेस केंद्र (HWC)
(PHC)
/ प्राथमिक चिकित्सालय
(iii) आयुष चिकित्सालय

प्राथमिक ~~विकास~~ चिकित्सा के लोकतांत्रिकरण की आवश्यकता
→

समान

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

① महिलाओं को परामर्श तथा संबंधित सेवायें प्रदान करने में।

② रोकथाम (Preventive health care) आधारित स्वास्थ्य सेवायें।

③ परिवार नियोजन कार्यक्रम का पुरुषों में विस्तार।

④ मुफ्त तथा सार्वभौमिक चिकित्सा का अधिकार प्रदान करना।

~~व्यापक देखभाल~~

⑤ आदिवासी पारम्परिक औषधियों तथा सांस्कृतिक वैद्यों को आधुनिक चिकित्सा तंत्र में शामिल करना।

व्यापक देखभाल

① बाल स्वास्थ्य
② महिला व प्रसूति स्वास्थ्य
③ बुजुर्ग स्वास्थ्य

} समेकित दृष्टिकोण

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

आगे की राह

→ स्वास्थ्य का एकीकृत तथा व्यापक दृष्टिकोण हो जिसमें :→

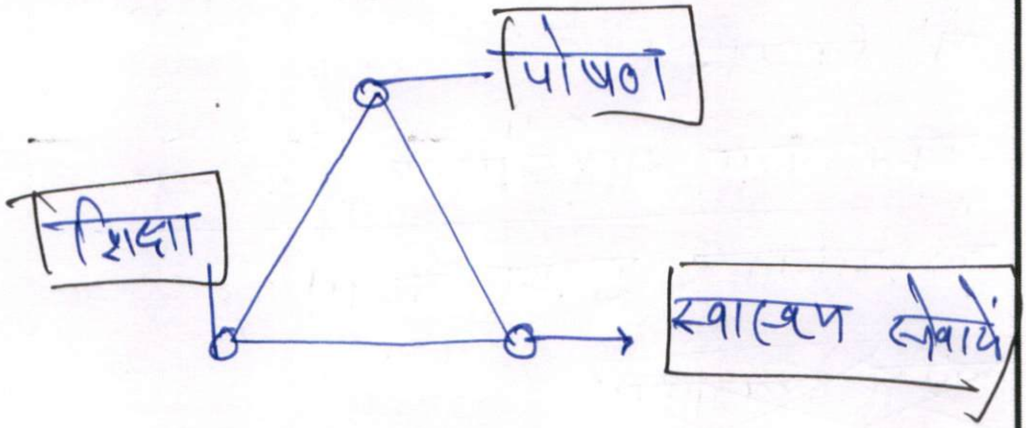

संविधान का अनुच्छेद- 21 तथा अनुच्छेद -47 एक प्रकार से स्वास्थ्य को महत्व तथा मानवीय गरिमा का अंग मानता है।

19. In the context of the evolving discourse on the Indo-Pacific, analyse the factors driving the global shift towards the region. Also, identify India's interests and challenges in this regard. **(250 words) 15**

हिंद-प्रशांत (इंडो-पसिफिक) पर विकसित हो रहे संवाद के संदर्भ में, इस क्षेत्र की ओर वैश्विक झुकाव को प्रेरित करने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए। साथ ही, इस संबंध में भारत के हितों और चुनौतियों की भी पहचान कीजिए।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र विश्व की 60% आबादी तथा 70% व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है।

वैश्विक झुकाव के कारण

① चीन का विस्तारवादी रवैय्या

② चीन द्वारा अमेरिकी एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौति देना

③ यह सदी (21वीं) एशियाई सदी है और हिंद प्रशांत क्षेत्र इसकी धुरी है।

④ विश्व के सबसे बड़े तथा सबसे तेजी से वृद्धि करते राष्ट्र की अवस्थिति एक आर्थिक अवसर

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

प्रदान करती है।

⑤ विश्व के प्रमुख व्यापार मार्गों का इस क्षेत्र में स्थित होना।

प्रमुख वैश्विक घटनाक्रम
हिंद प्रशांत के संदर्भ में

① (QUAD) क्वाड का निर्माण
भारत, अमेरिका, जापान तथा आस्ट्रेलिया

② AUKUS का निर्माण आस्ट्रेलिया ब्रिटेन तथा अमेरिका के बीच।

भारत के हित

① भारत हिंद-प्रशांत में एक नेट सुरक्षा प्रदाता की भूमिका अदा करता आया है

② भारत के ब्लू-इकोनॉमी, मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण

② भारत के 95% व्यापार का हिंद-प्रशांत क्षेत्र से होना।

③ भारत की भौगोलिक अवस्थिति इसे हिंद-प्रशांत में व्यापक भूमिका हेतु प्रेरित करती है।

④ चीन के 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल' तथा विस्तारवाद का मुकाबला करने के लिये जरूरी।

चुनौतियाँ → ① भारत की नौसैनिक शक्ति का कमजोर होना (चीन के मुकाबले)

② अमेरिका का भरोसेमंद मित्र न होना

③ AUKUS में भारत को शामिल न किया जाना।

④ चीन का पाकिस्तान गठजोड़।

⑤ रूस का इस क्षेत्र में भारत को समर्थन न होना।

भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को ध्यान में रखकर इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की जरूरत।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. India's Afghanistan policy must be based on a clear-eyed understanding of important strategic goals in the region amidst the current regional and global strategic environment. Elaborate. **(250 words) 15**

भारत की अफगानिस्तान नीति वर्तमान क्षेत्रीय और वैश्विक रणनीतिक परिवेश के बीच इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण रणनीतिक लक्ष्यों की स्पष्ट समझ पर आधारित होनी चाहिए। सविस्तार वर्णन कीजिए।

हाल ही में अफगानिस्तान पर तालिबान ने पुनः कब्जा कर सत्ता स्थापित कर ली। जिससे भारत हेतु चिंताजनक स्थितियाँ उत्पन्न हुयीं हैं।

भारत के लिये उत्पन्न चुनौतियाँ

① तालिबान का पाकिस्तान की ISI के साथ पुराना गठजोड़।

② तालिबान से आतंकवाद का कश्मीर में फैलाव हो सकता है

③ अफगानिस्तान - पाकिस्तान के जरिये भारत में अफीम की तस्करी बढ़ेगी (गोल्डन क्रिसेंट)

[उदाहरण- गुजरात से बरामद 3000kg हेरोइन (Oct 2021)]

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(4) भारत की विकास परियोजनाओं तथा लगभग 25,000 करोड़ के निवेश को खतरा।

(5) संभावित शरणार्थी संकट

भारत की वर्तमान अफगानिस्तान रणनीति :→

भारत वर्तमान में तेजी से बदलते घटनाक्रम में धीरे-2 आगे बढ़ रहा है मुख्यत: भारत अभी "वेट एंड ~~वाच~~ वॉच" की नीति का पालन कर रहा है

वैश्विक रणनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप अफगान रणनीति क्या होनी चाहिये?

(7) अफगानिस्तान के मानवीय संकट में मदद करनी चाहिये।

(8) पूर्व के अनुभवों के खुद पर हावी न होने देकर "स्वतंत्र तौर

पर नये सिरे से तालीबान से संबंध बनाने चाहिये।

(3) भारत की चाहबार तथा अफगान परियोजनाओं को तालिबान से मिलकर संरक्षण देना चाहिये।

(4) अगर भारत इस योग से पीछे हटेगा तो चीन भारत का स्थान ले सकता है

भारत को रूस तथा SCO के माध्यम से तालिबान से संवाद स्थापित कर क्षेत्रीय शांति व सहयोग बढ़ाना चाहिये।